नईदुनिया



शेख हसीना के गृह जिला गोपालगंज में अवामी लीग के जुलूस पर विवाद, बम चले, दुकानें फूंकी, 30 घायल

ढाका (बांग्लादेश)

अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का पैतृक गृह जनपद और देश के राजनीतिक गढ़ के रूप में मशहूर गोपालगंज में जमकर देसी बम फूटे। कम से कम 12 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान लगभग 30 लोग घायल हो गए। यह घटनाएं हसीना की पार्टी अवामी लीग और उससे संबद्ध संगठनों के दिन में निकाले गए जुलूस को लेकर हुए विवाद के बाद हुईं।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधित अवामी लीग के गोपालगंज शहर व अन्य स्थानों पर निकाले गए जुलूस पर हुए विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। यह खूनखराबा गोपालगंज शहर के लान्च घाट और गोपालगंज क्रिकेट स्टेडियम के आसपास के इलाकों और कोतालीपाड़ा उपजिला के दक्षिण हिरन गांव में हुआ।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज शहर के लान्च घाट इलाके से एक जुलूस निकाला। जुलूस के बाद एक रैली में पार्टी नेताओं के बगल में खड़े होने को लेकर घोषरचर गांव के एक युवक और चारमानिकदाह गांव के कुछ युवकों के बीच बहस हो गई। इस घटना के कारण शाम को दोनों गांवों के निवासियों के बीच झड़पें शुरू हो गईं।

गोपालगंज क्रिकेट स्टेडियम के पास की सड़क पर दोनों गुटों के बीच देसी हथियारों के साथ आमना-सामना हुआ और एक-दूसरे का पीछा किया गया। झड़प के दौरान चार देसी बम फटे और फूलों की कम से कम सात दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस घटना में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इनमें से पांच गंभीर रूप से घायल लोगों को गोपालगंज मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया। गोपालगंज मेडिकल कालेज अस्पताल के सहायक निदेशक डा. नियाज़ महमूद ने बताया कि शाम को एक झड़प में घायल हुए कई लोग अस्पताल आए। कुछ लोग प्राथमिक उपचार के बाद चले गए, जबकि कई अन्य अस्पताल में भर्ती रहे।

गोपालगंज सदर थाना के इंस्पेक्टर (जांच) मो. सिराजुल इस्लाम ने कहा, हमें घटना के बारे में शुरुआती जानकारी मिली है। अभी तक किसी ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अगर कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है,तो जांच के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, कोतालीपाड़ा उपजिला के दक्षिण हिरन गांव में अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के निकाले गए जुलूस को लेकर दो गुटों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद झड़प हो गई। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए और पांच दुकानों में तोड़फोड़ की गई।

न्यूज ब्रीफ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने की यूक्रेन युद्ध खत्म करने की मांग



संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए। काला सागर में जहाजों और खाद्य की आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि यूक्रेन युद्ध पांचवें वर्ष में पहुंच चुका है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत के स्थाई प्रतिनिधि पी हरीश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया को कभी न खत्म होने वाले युद्ध से आगे बढ़कर युद्ध के अंत की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और काला सागर क्षेत्र मिलकर दुनिया के करीब 20 फीसद अनाज का उत्पादन करते हैं। रूस और यूक्रेन दुनिया के गेहूं, मक्का और जौ के कुल निर्यात में करीब 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं। पी हरीश ने कहा कि युद्ध से खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट बढ़ा है। इससे विकासशील देश (ग्लोबल साउथ के देश) सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भारत के 1943 के बंगाल अकाल का जिक्र किया, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने इस अवसर पर काला सागर में जहाजों पर हमलों में अब तक चार भारतीय नाविकों की मौत और दो लापता होने का जिक्र किया।

अयोध्या से जनकपुरधाम पहुंची सरयू-कमला एक्सप्रेस, भारत-नेपाल के बीच शुरू हुई रामायण सर्किट रेल सेवा



काठमांडू। भारत और नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में शुरू की गई सरयू-कमला एक्सप्रेस मंगलवार सुबह नेपाल के जनकपुरधाम पहुंच गई। भारत के अयोध्या से रवाना हुई यह ट्रेन मंगलवार सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर जनकपुरधाम रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के पहुंचने पर यात्रियों का फूल-मालाओं और भारत-नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वागत किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने संयुक्त रूप से इस रेल सेवा का उद्घाटन किया । यह अयोध्या से जनकपुरधाम के लिए रवाना हुई । करीब 21 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद ट्रेन जनकपुरधाम पहुंची। ट्रेन में सवार यात्रियों के आगमन को लेकर जनकपुरधाम में उत्साह का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं और दोनों देशों के झंडों के साथ यात्रियों का स्वागत किया। सरयू-कमला एक्सप्रेस रेल सेवा को भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसके माध्यम से अयोध्या और जनकपुर जैसे रामायण परंपरा से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है। जनकपुरधाम को माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है। रामायण परंपरा में दोनों शहरों का विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस रेल सेवा से दोनों देशों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा में सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, भारत और नेपाल के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जनस्तर पर संपर्क को भी बढ़ावा मिल सकता है।

ट्रंप ने ईरान को दी धमकी कहा- नए साल पर तबाही मचाएंगे

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नए साल तक दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो ईरान पर दोबारा सैन्य हमला किया जाएगा। ट्रंप ने बातचीत को लेकर ईरान के रवैये की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेहरान के अधिकारी बात घुमाने में माहिर हैं और वे सिर्फ बातें करते हैं, जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। ट्रंप ने ईरान को यह भी चेताया कि यदि ईरानी टैंकर समुद्री नाकेबंदी को तोड़ते हैं, तो उनका हश्र भी ईरान की नौसेना की तरह समुद्र की तलहटी में होगा। अमेरिका और ईरान के बीच बीते फरवरी महीने से ही जंग जारी है। कतर, ओमान और पाकिस्तान जैसे देशों की मध्यस्थता के बाद भी कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है। दोनों ओर से अब भी हमले जारी हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप कई बार ईरान द्वारा बातचीत में रखी जा रही शर्तों पर असंतोष व्यक्त कर चुके हैं। इससे एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा था कि अगर अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप उचित शर्तें स्वीकार कर ले, तो होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अराघची ने जोर दिया कि संकट के समाधान के लिए वाशिंगटन को अपनी गलतियां स्वीकार करनी होंगी और उसे पहले किए गए अपने सभी वादों को पूरा करना होगा। इस बीच, ईरान भी शांत नहीं बैठा है और अपनी सैन्य शक्ति का लगातार प्रदर्शन कर रहा है।

जेन्सेन हुआंग की एनवीडिया में वापसी तो हुई पर संदेह के बादल छंटे नहीं, अगले सप्ताह अमेरिकी कांग्रेस के सामने देनी होगी गवाही

वाशिंगटन (अमेरिका)

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया में जेन्सेन हुआंग की वापसी से विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी कांग्रेस (संसद) की कई समितियों ने पुष्टि की है कि हुआंग अगले सप्ताह सांसदों के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देंगे। इस मामले में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों दलों के सांसदों ने चिंता जताई है। एनवीडिया के पूर्व प्रमुख जेन्सेन हुआंग को फिर कंपनी का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और निदेशक मंडल का सदस्य नियुक्त करने पर गंभीर सवाल उठे हैं।

एक्सिओस और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार. हुआंग ने इस महीने की शुरुआत में निजी संबंधों से जुड़े विवादों और कथित चीनी जासूसी संपर्कों की खबरों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, 23 नवंबर को कंपनी के निदेशक मंडल ने उन्हें फिर से कंपनी का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी वापसी का स्वागत किया है। बताया गया है कि हुआंग पहली दिसंबर को प्रतिनिधि सभा की तीन समितियों के सामने पेश होंगे। इनमें खुफिया मामलों की समिति, विदेश मामलों की समिति और चीन से जुड़े मामलों की विशेष समिति शामिल हैं।

इसके अलावा, सीनेट की बैंकिंग समिति ने भी उन्हें तीन दिसंबर को गवाही के लिए तलब किया है। खबर है कि एनवीडिया के जनरल काउंसिल टिम टीटर दो दिसंबर को इन समितियों के सामने स्वेच्छा से अपना पक्ष रखने पर सहमत हो गए हैं। खुफिया मामलों की समिति के प्रवक्ता ने कहा कि हुआंग को दोबारा सीईओ बनाए जाने से कांग्रेस की जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समिति का कहना है कि कंपनी के प्रमुख रहते हुए भी उनसे सवाल पूछे जाने थे और पद छोड़ने के बाद भी जांच जारी थी। अब उनकी वापसी से भी स्थिति नहीं बदलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं।

सांसदों ने जताई नाराजगी: सीनेट में विपक्ष के नेता चक शूमर ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप प्रशासन, जेन्सेन हुआंग और एनवीडिया के अन्य अधिकारियों से जुड़े किसी भी गलत काम की जांच के लिए पूरी ताकत लगाएगी। सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने भी कहा कि हुआंग की वापसी से कंपनी की जवाबदेही खत्म नहीं हो



जाती। कंपनी के अधिकारियों और निदेशक मंडल को कांग्रेस के सामने जवाब देना होगा।

उन्होंने निर्यात नियंत्रण से जुड़े कानूनों को जल्द लागू करने की जरूरत भी बताई। उनका कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनवीडिया ऐसे कानूनों को रोकने के लिए दबाव न बनाए, जिनका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है।

प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने हुआंग की वापसी के फैसले को अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कंपनी और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक की भूमिका की व्यापक जांच कराने की मांग की है। कैलिफोर्निया के सांसद राबर्ट गार्सिया ने भी इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप की कथित भूमिका पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि किसी राष्ट्रपति का किसी निजी कंपनी में निवेश है, तो उसे उस कंपनी के बोर्ड के फैसलों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

रिपब्लिकन सांसदों ने भी उठाए सवाल: हुआंग की वापसी को लेकर केवल डेमोक्रेटिक सांसद ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने भी कंपनी के फैसले पर संदेह जताया है। टेक्सास के सीनेटर जान कार्निन ने कंपनी बोर्ड के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। यूटा के सीनेटर जान कर्टिस ने भी पूछा कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि कुछ ही दिनों में बोर्ड ने अपना फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि पहले कंपनी ने हुआंग को वापस लाने की कोई योजना नहीं होने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्हें फिर से सीईओ बना दिया गया। यह सब उस समय हुआ है, जब उनके खिलाफ स्वतंत्र जांच अभी जारी है। नार्थ डकोटा के सीनेटर केविन क्रेमर ने तो हुआंग की दोबारा नियुक्ति पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए उन्हें फिर से कंपनी की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। क्रेमर ने अमेरिका में निर्यात नियंत्रण कानूनों को और सख्त बनाने की मांग की।

चीन को चिप निर्यात भी जांच के दायरे में: इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू एनवीडिया के चिप निर्यात से जुड़ा है। अमेरिकी सांसद यह जानना चाहते हैं कि कंपनी ने चीन सहित दूसरे देशों को अपने अत्याधुनिक चिप बेचने के दौरान अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन किया या नहीं। अमेरिकी सरकार को आशंका है कि अत्याधुनिक चिप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़ी तकनीक चीन की सैन्य और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका ने चीन को कुछ उन्नत चिप बेचने पर प्रतिबंध और नियंत्रण लगा रखे हैं। अब कांग्रेस की सुनवाई में हुआंग से कंपनी की कारोबारी नीतियों, चीन को चिप निर्यात और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सवाल पूछे जाने की संभावना है।

ट्रंप की अपील का असर: कंपनी के अनुसार, बोर्ड ने हुआंग के साथ कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद उनकी वापसी का फैसला किया। बोर्ड का कहना है कि उसे हुआंग की स्पष्टवादिता और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है। इस फैसले से पहले अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी राय ली गई। हुआंग की वापसी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। ट्रंप लगातार कंपनी के बोर्ड से उन्हें फिर से कंपनी की कमान सौंपने की अपील कर रहे थे।

इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी अलग-अलग राय सामने आई थी। वित्त सचिव स्काट बेसेंट ने शुरुआत में कंपनी में नए बाहरी सीईओ और बड़े बदलाव की जरूरत बताई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना रुख नरम कर लिया। दूसरी ओर, वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक की चीन को एनवीडिया के चिप निर्यात से जुड़े फैसलों को लेकर आलोचना हुई थी। इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के बीच मतभेद भी सामने आए।

सर्बिया में नौकरी का झांसा देकर दिल्ली के होटल में 45 दिन तक बंधक बनाकर रखे गए नेपाल के तीन नागरिकों को मुक्त कराया गया



काठमांडू

विदेश में अच्छी नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर सर्बिया भेजने के बहाने दिल्ली लाकर नेपाल के तीन नागरिकों को करीब 45 दिन तक एक होटल के कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। नेपाल पुलिस, नेपाली दूतावास, दिल्ली पुलिस और एक सामाजिक संस्था के संयुक्त प्रयास से तीनों को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया।

सगरमाथा पर्वतारोही कल्पना महर्जन के अनुसार, तीनों नागरिकों को सर्बिया में रोजगार दिलाने का प्रलोभन देकर नई दिल्ली पहुंटाया गया । यहां उन्हें एक होटल के कमरे में बंधक बनाकर रखा गया । इसकी सूचना मिलने पर नेपाल पुलिस के मानव तस्करी जांच ब्यूरो, नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास, दिल्ली पुलिस और सामाजिक संस्था किन इंडिया ने कार्रवाई शुरू की। संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय और संयुक्त प्रयास के बाद तीनों नेपाली नागरिकों को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया। इन तीनों को नेपाली दूतावास के सहयोग से मंगलवार सुबह काठमांडू पहुंचाया गया। वहां उनसे पूछताछ की जा रही है।

सामाजिक संस्था किन इंडिया के निदेशक नवीन जोशी के अनुसार, एक अवैध मानव तस्करी गिरोह ने तीनों नेपाली नागरिकों को विदेश में रोजगार दिलाने का आश्वासन देकर दिल्ली पहुंचाया। उन्हें सर्बिया भेजने का प्रलोभन दिया गया और दिल्ली के एक होटल में बंधक बनाकर रखा गया।

जोशी ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद संबंधित सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों से तत्काल संपर्क कर तीनों की सुरक्षित रिहाई के लिए पहल की गई। उन्होंने कहा कि विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर नेपाली नागरिकों को शोषण और मानव तस्करी के जोखिम में डालने वाली ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सरकारी निकायों को अधिक सतर्क और जिम्मेदार होना होगा।

इस घटना ने एक बार फिर विदेश में रोजगार के नाम पर नेपाली नागरिकों को निशाना बनाने वाले मानव तस्करी गिरोहों के खतरे को उजागर किया है।

नेपाल में तिब्बत की सीमा से सटे क्षेत्र में 5.6 तीव्रता का भूकंप



काठमांडू। नेपाल के पूर्वी सीमा क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका असर सिक्किम में भी महसूस किया गया।रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 दर्ज की गई। राष्ट्रीय भूकंप मापन एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, भूकंप सुबह 7 बजकर 17 मिनट पर आया। इसका केंद्र नेपाल के ताप्लेजुंग जिले के ओलांगचुंग गोला के निकट रही। यह इलाका तिब्बत की सीमा से सटा हुआ है। केंद्र के भूकंप विज्ञानी राजेश शर्मा ने बताया कि भूकंप के झटके कोशी प्रदेश के कुछ जिलों में भी महसूस किए गए। हालांकि, भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने भूकंप के केंद्र को भारत के सिक्किम राज्य के मंगन क्षेत्र से लगभग 67 किलोमीटर दूर बताया है और कहा कि इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था।

रक्सौल-काठमांडू रेलमार्ग का फील्ड लोकेशन सर्वे पूरा, अब डीपीआर तैयार करने पर नेपाल-भारत के बीच सहमति

काठमांडू

नेपाल की राजधानी काठमांडू को भारत के सीमावर्ती शहर रक्सौल से जोड़ने वाली प्रस्तावित विद्युतीय रेल परियोजना ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। काठमांडू-रक्सौल रेलमार्ग का फील्ड लोकेशन सर्वे (स्थलीरय सर्वेक्षण) पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इसकी आधिकारिक घोषणा की।

भारत और नेपाल की ओर से जारी संयुक्त विजन पेपर में कहा गया है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने प्रस्तावित रक्सौल-काठमांडू इलेक्ट्रिक ब्राडगेज रेलमार्ग का फील्ड लोकेशन सर्वे पूरा होने की घोषणा की है। सर्वे पूरा होने के बाद अब इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, रेलमार्ग के निर्माण की लागत और निवेश का प्रारूप अभी तय नहीं हुआ है।

2018 में हुआ था रेल संपर्क विस्तार पर समझौता

नेपाल और भारत के बीच 7 अप्रैल 2018 को रेल संपर्क विस्तार को लेकर सहमति बनी थी। इसी समझौते के तहत भारत के सीमावर्ती शहर रक्सौल को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने के लिए नई विद्युतीय रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस परियोजना का वित्तीय प्रबंधन भारत की ओर से किए जाने की बात कही गई थी। फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 8 अक्टूबर 2021 को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता (एमओयू) हुआ था। इसके तहत भारत की आर्थिक और तकनीकी सहायता से सर्वे का काम आगे बढ़ाया गया। भारत ने वर्ष 2023 में ही इस रेलमार्ग का फाइनल लोकेशन सर्वे तैयार कर नेपाल सरकार से उस पर राय और सुझाव मांगे थे। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी 20 मार्च 2026 को राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि रक्सौल-काठमांडू रेलमार्ग का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो चुका है। उस समय उन्होंने इसकी लंबाई 136 किलोमीटर बताई थी। हालांकि, प्रधानमंत्री



शाह की भारत यात्रा के दौरान जारी जानकारी के अनुसार, सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट में रेलमार्ग की लंबाई 140.79 किलोमीटर बताई गई है।

41 किलोमीटर हिस्से में बनेंगी सुरंगें

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित रेलमार्ग का लगभग 41 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा, जबकि शेष हिस्सा जमीन की सतह पर बनाया जाएगा। इस रेल परियोजना के तहत 122 छोटे और 101 बड़े पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें 18 लंबे और जटिल प्रकृति के पुल भी शामिल हैं। इन पुलों के ऊपर से रेल लाइन गुजरेगी। नेपाल के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय ने फाइनल लोकेशन सर्वे के दौरान भारत को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। नेपाल ने प्रस्तावित निजगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और खनन क्षेत्रों को प्रभावित किए बिना रेलमार्ग का डिजाइन तैयार करने का सुझाव दिया था।

बांग्लादेश में धरपकड़ तेज, ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर हमले, पूर्व सांसद गिरफ्तार

ढाका (बांग्लादेश)

अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिसंबर में देश लौटने की घोषणा के बाद मची हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बाद घबराई सरकार ने विपक्षी नेताओं से मंत्रणा शुरू कर दी है। दूसरी ओर प्रतिबंधित अवामी लीग के नेताओं और अन्य के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। इस बीच अंतरिम सरकार के पूर्व मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया है कि नवंबर की शुरुआत से ही ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर लगभग हर दिन पेट्रोल बम से हमले किए जा रहे हैं।

अकेले इसी महीने देश भर में बैंक की लगभग 100 शाखाओं पर इसी तरह से हमले किए गए हैं। इस सबके बीच पुलिस ने एक और पूर्व सांसद को गिरफ्तार किया है।

प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के जेस्सोर-6 निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व सांसद मो. अजीजुल इस्लाम को डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) पुलिस ने लालमाटिया से गिरफ्तार किया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया। डीबी पुलिस के तेजगांव डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अजीजुल इस्लाम को डीबी कार्यालय लाया गया।



गिरफ्तार पूर्व सांसद अजीजुल इस्लाम 33 वर्ष के हैं। उनका घर जेस्सोर के केशवपुर में है। डीबी पुलिस के अनुसार, जेस्सोर में अजीजुल के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। अजीजुल इस्लाम ने 2024 के 12वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में जेस्सोर-6 (केशवपुर) निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। उन्होंने अवामी लीग के उम्मीदवार और जेस्सोर जिला अवामी लीग के महासचिव शाहीन चकलादर को हराया था। माना जाता है कि अजीजुल इस्लाम को केशवपुर की पूर्व सांसद और पूर्व लोक प्रशासन राज्यमंत्री दिवंगत इस्मत आरा सादेक का समर्थन प्राप्त था। अजीजुल इस्लाम एक समय वे केशवपुर उपजिला में छात्र लीग के संयुक्त संयोजक थे। बाद में, वे जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए । बांग्लादेश में छात्र लीग अब प्रतिबंधित है। अंतरिम सरकार के पूर्व मुख्य सलाहकार प्रो. यूनुस ने ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर हो रहे हमलों को रोकने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। प्रोफेसर के अनुसार, बैंक शाखाओं पर हमले के दौरान जय बांग्ला के नारे लगाए जा रहे हैं। इस माह अब तक 100 शाखाओं पर हमले हो चुके हैं। यूनुस ने ग्रामीण बैंक पर हो रहे लगातार हमलों को गरीब महिलाओं की सुरक्षा और आजादी, तथा उनके बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक के 1.1 करोड़ (11 मिलियन) कर्जदारों में से 97 प्रतिशत महिलाएं हैं। बैंक का लोन रिकवरी रेट 95 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि ये महिला कर्जदार ही बैंक की मालिक हैं। प्रोफेसर यूनुस ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण बैंक के के 90 प्रतिशत शेयर कर्जदारों के पास हैं, जबकि बाकी 10 प्रतिशत शेयर सरकार के पास हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि अवामी लीग सरकार ने 2011 में उन्हें ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया था।